1-06-14 दैनिक जागरण

मनरेगा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नया प्रशासनिक तंत्र

राज्य ब्यूरो, पटना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बेहतर कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नया प्रशासनिक तंत्र विकसित करने का फैसला लिया है। मुख्यालय में एक कोर टीम मनरेगा की मानिटरिंग के लिए मौजूद रहेगी। कोर टीम के 161 पदों का ग्रामीण विकास विभाग ने सृजन कर दिया है। इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों, सहायक अभियंताओं आदि के रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण मंत्री नीतीश मिश्रा के निर्देश पर इस

161 सदस्यीय कोर टीम रखेगी नजर, पद सृजित

संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि मनरेगा योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाने का प्रमुख कारण निचले स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र में पर्याप्त कर्मियों का नहीं होना है। वर्तमान में 8436 पंचायतों के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी के 534, प्रखंड स्तर के लेखापाल के 534, कनीय अभियंता के 846, पंचायत तकनीकी सहायक के 1057 एवं पंचायत रोजगार सेवक के 8463 पद स्वीकृत हैं। मात्र इतने पदों से मनरेगा के कार्यक्रम को वृहत स्तर पर चलाना और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में कार्यक्रम पदाधिकारी के 393, कार्यपालक अभियंता के 16, कनीय अभियंता के 1290, सहायक अभियंता के 78 एवं पंचायत तकनीकी सहायक के 107 अतिरिक्त पदों तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 38 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा कोर टीम के लिए 161 पद सृजित किए गए हैं। इसपर आने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से 139.30 करोड़ की राशि देगी।